

नं. ओ. वि./एफ.डी./गुड़गांव/16—86/33659—चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं 1. उपायुक्त, गुड़गांव, 2. प्रशासक, नगरपालिका ताड़ड़, (गुड़गांव) के श्रमिक श्री हरपाल मिह, पुत्र श्री जिवराम, गांव ताड़ड़, पीछे मुसाफ मार्केट, गुड़गांव तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई आद्योगिक विवाद है।

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं।

इसलिये अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5115-3-अम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-अम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करने हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री हरपाल मिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस ग्राहक का हकदार है?

नं. ओ. वि. भिवानी/82—86/33667—चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं जनरल आफिसर कमान्डिंग मुख्यालय, पी. एच. एण्ड एच. पी. एरिया, शिमला (हिमाचल) 2. गॉन्डन वार्डन, पी. एच. एण्ड एच. पी. एरिया केंद्रीयत, भिवानी के श्रमिक श्री ब्रिज मिह, पुत्र श्री तर्धामह, गांव हलवाम, तहसील बजिला भिवानी तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं।

इस लिये अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9841-1-अम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1971 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करने हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है।

क्या श्री ब्रिज मिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस ग्राहक का हकदार है?

दिनांक 16 नितम्बर, 1986

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/79—86/33644—चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़, 2. जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, गुड़गांव के श्रमिक श्री राजपाल, पुत्र श्री पूरन मिह, गांव मन्दवार, बा. धोला तहसील सोहना, जिला गुड़गांव तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं।

इसलिये अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5115-3-अम 68/15254, दिनांक 20 जून 1978 के साथ पढते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करने हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री राजपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस ग्राहक का हकदार है?

आर. एम. अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।